

अनुगामिनी

ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल 8 बाधाएं हमें रोक नहीं पाएंगी, हम भारत को जोड़ेंगे : राहुल 3

देश के विकास के लिए गांवों का विकास जरूरी : राज्यपाल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 13 सितम्बर ।

सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने आज पूर्व सिक्किम में तुम्हारा-नामराग का दीरा किया जहां उन्होंने 'नामराग मनोकामना फॉल्स' की ओर जाने वाले फुटपथ का उद्घाटन किया।

गोरतलब है कि गंगटोक से करीब 25 किमी दूर नामराग में गत जुलाई में अपने दोस्रे के दोरान राज्यपाल ने यहां के ढाँचागत विकास कार्य हेतु अधिक मरद का आश्वासन दिया था। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नामराग को एक प्रसिद्ध पर्वत स्थल के तौर पर विकसित करने में भी रुचि दिखायी थी। उसके बाद ही राज्य के कोष से नामराग के नवजीवी संघ नामक एनाइओ को

इस कार्य हेतु 6 लाख रुपए की धनराशि मुहूर्या करायी गयी।

आज इस उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में खेत्रीय प्रभारी सामुद्र भूटिया, एडीपी (विकास) राधा प्रधान, सरकारी-तिरोक के बीड़ीओ किशोर थापा के अलावा स्थानीय वार्ड पंचायत रोहितराज लुटेल, नवज्ञति संघ के अध्यक्ष लोकनाथ सापकोटा, नामराग जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग शामिल हुए।

वार्ड पंचायत रोहितराज लुटेल ने अपने स्वगत भाषण में बताया कि यह राज्य विकास कार्यों पर खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचा



विकास पर 3 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने नामराग जूनियर हाई स्कूल के कार्य के बारे में भी बताया।

वर्ही राज्यपाल ने अपने संक्षिप्त सम्बोधन में कहा कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है।

चाहिए।

साथ ही उन्होंने नशीली दवाओं के सेवन के दुष्प्रभावों से आग्रह किया और कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाएं सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु काम करने के लिए प्रभावी होनी चाहिए।

**केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने की घोषणा
सिविकम में बनेगा 100 शव्या वाला ईएमआई अस्पताल**



अनुगामिनी नि.सं. पाकिम, 13 सितम्बर। केंद्रीय श्रम व रोजगार तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार विभिन्न क्षेत्रों में नए मील के पथर स्थापित कर रही है।

कार्यक्रम में श्रम मंत्री लोकनाथ शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को 100 शव्याओं वाले ईएमआई अस्पताल बनाने की घोषणा हेतु धन्यवाद दिया।

बाद में केंद्रीय मंत्री ने राक्षदोण प्रखण्ड प्रशासनिक केंद्र का भी दौरा किया। वहां सरकारी तिनेके के बीड़ीओ किशोर थापा को शामिल होना भी उनका एक अंतर्गत कार्य।

वर्ही मजदूरों को समर्पित कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को श्रमिकों का पंजीकरण में इंडियन ऑफियल कॉर्पोरेशन परिसर में उज्ज्वला योजना के लाभान्वितों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन तथा ई-श्रम कार्ड प्रदान करने में उत्तमता दी।

उन्होंने श्रमिकों के लिए 100 शव्या वाला ईएमआई अस्पताल करने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने नवनिर्मित फाइबर सिलिंडरों के फायदे भी बताये।

कार्यक्रम में श्रम मंत्री लोकनाथ शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को 100 शव्याओं वाले ईएमआई अस्पताल बनाने की घोषणा हेतु धन्यवाद दिया।

बाद में केंद्रीय मंत्री ने राक्षदोण प्रखण्ड प्रशासनिक केंद्र का भी दौरा किया। वहां सरकारी तिनेके के बीड़ीओ किशोर थापा ने उनका स्वागत किया।

वर्ही बीड़ीओ में एक बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कम से कम दो लाख लोगों का ई-श्रम कार्ड मुहूर्या करने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित फाइबर सिलिंडरों के फायदे भी बताये।

उन्होंने श्रमिकों के लिए लाभ के प्रावधान को केंद्रीय राज्य मंत्री तेली ने अपने सम्बोधन में राज्य और उन्हें इसका हकदार बनने के लिए पंजीकृत होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ई-श्रम कार्ड के लाभों पर भी प्रकाश डाला और लक्षित लाभान्वितों को ई-श्रम

371एफ के खिलाफ बयान पर विवाद और गहराया समयबद्ध जांच कर पुलिस करे

कार्टवाई

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 13 सितम्बर। दिल्ली के जंतर-मंतर में दो व्यक्तियों द्वारा एक सदस्य है, जिसका नेता यति नरसिंहानंद सरस्वती है। वर्ही राज्यपाल ने अपने संविधान की धारा 371एफ हटाने तथा राज्य व राज्यवासियों के बारे में अनगल टिप्पणी करते हुए योग्योंसे साझा करने का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है।

हायो सिक्किम पार्टी ने इस मामले की पूरी जांच करते हुए इसमें सीधे तौर पर तथा पर्यंत के पीछे से शामिल लोगों को सामने लाने की मांग की है।

हायो सिक्किम पार्टी के महासचिव अधिकारी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस वीडियो के जारी किये जाने के बाद ही 8 सितम्बर को हमारे पार्टी नेता भाइचंग भूटिया ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि इसके पीछे राज्य तथा राज्य के बारे में कुछ गलत वाचाकी थी। इसके पीछे से शामिल लोगों को सामने लाने की मांग की है।

हायो सिक्किम पार्टी के महासचिव अधिकारी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस वीडियो के जारी किये जाने के बाद ही 8 सितम्बर को हमारे पार्टी नेता भाइचंग भूटिया ने एक वीडियो में सुमंत कुमार करते दिख रहे हैं कि भाजपा समेत कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उसे बाईंदी ही हैं और सिक्किम में सीएए तथा एनआरसी लागू करने के साथ ही पश्चिम बंगाल में राज्य के विलय की मांग उठाने को कहा है।

उन्होंने उपर्याद जारी किया कि इसी वजह से राज्य में बुसपैट बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ शांति और भईचारा की बात करने से नहीं है। उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहा एक युवक सुमंत कुमार ऊर्जा

मामले की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने अपना दर्जा किया कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काटने वाले और चबाने वाले दांत अलग-अलग होते हैं।

'भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का साथ', एनसीपीसीआर ने की चुनाव आयोग से शिकायत

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसी)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा' में बच्चों का कथित रूप से राजनीतिक साधन के रूप में दुरुपयोग करने के मामले में पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई तथा जांच की जाए। एनसीपीसीआर ने शिकायत की पावती में यह बताया गया है कि इसका उल्लंघन है जिनमें देखा जा सकता है कि भारत जोड़ो, बच्चे जोड़ो' नारे के तहत बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और राजनीतिक संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है।'

आयोग आपसे अनुरोध करता है कि इस मामले को देखें तथा घटनाक्रम की पूरी पढ़ताल करें और शिकायत में जिस राजनीतिक दल और उसके सदस्यों का उल्लेख किया गया है तुनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने पार्टी के निशाना बना रखे हैं और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं।

आयोग आपसे अनुरोध करता है कि यह निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है जिनमें कहा गया है कि केवल वयस्क ही किसी राजनीतिक दल का हिस्सा हो सकते हैं। आयोग ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में बताया, यह बाल अधिकारों का प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन है।

शुरू हुई यह यात्रा पांच महीने की दूरी तक 3,570 किलोमीटर की दूरी तक अवधि में कन्याकुमारी से कश्मीर करेगी।

मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा रखा है : गहलोत



जयपुर, 13 सितम्बर (एजेंसी)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने सीबीआई और अधिकार विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा रखा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीते आठ साल में इन एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक भी व्यक्ति पर छापा नहीं मारा जबकि बाकी लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नावा (नागर) में एक कार्यक्रम को संबोधित करना और इसे

उन्होंने कहा, इन एजेंसियों (केंद्रीय जांच एजेंसियों) को छोड़कर रखा है भारत सरकार ने विपक्ष के ऊपर ... अधिकर विभाग ... सीबीआई ... हमने इन पर आरोप लगाया है कि आप इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपको आठ साल में एक व्यक्ति भाजपा का नहीं मिला जबकि भाजपा तो व्यापरियों की, उद्यमियों की, पैसे वालों की पार्टी मारी जाती है... आपने किसी भाजपा वाले पर छापा नहीं डाला... बाकी शिवसेना हो, सपा हो, कांग्रेस वाला हो या और कोई भी हो सब पर छापे पड़ रहे हैं देश

गहलोत के अनुसार, विधानसभा में हारे परिषेकी साथी कहते हैं कि (गहलोत सरकार का) बजट तो बहुत भारतीय लोकों और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

गहलोत के अनुसार, विधानसभा में हारे परिषेकी साथी कहते हैं कि आप इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपको आठ साल में एक व्यक्ति भाजपा तो व्यापरियों की, उद्यमियों की, पैसे वालों की पार्टी मारी जाती है... आपने किसी भाजपा वाले पर छापा नहीं डाला... बाकी शिवसेना हो, सपा हो, कांग्रेस वाला हो या और कोई भी हो सब पर छापे पड़ रहे हैं देश

महंगाई को लेकर केंद्र पर बरसे चिंदंबरम, वित्त मंत्री से पूछे सवाल



नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिंदंबरम ने खुदरा महंगाई दर का अपरिवर्तन दर का प्रतिशत होने को लेकर बालवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामण पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें इस स्थिति में भी खुदरा नहीं दिखाई देता है तो वह औपसत भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करती। पूर्व वित्त मंत्री ने टीवी किया, अभी कुछ दिन पहले ही, माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई उनके लिए चिंता को कोई बढ़ा दिया नहीं है। भारत की खुदरा महंगाई दर का बढ़कर सात प्रतिशत हुआ तुम्हारी उम्मीद थी। आपको आधारित युद्धान्वयन 6.71 प्रतिशत में 5.3 प्रतिशत थी।

वित्त मंत्री को अभी भी 'खतरा' दिखाई नहीं देता है, तो हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह भारत में औपसत परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। सभी, मासले जैसे खाने के सामान के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर अगस्त महीने में बढ़ कर सात प्रतिशत पर पहुंच गयी। इसके साथ पिछले तीन महीने से खुदरा मुद्रासंकरीति में आ रही कमी थम गयी है। सोमवार को जारी सरकारी अंकड़ों से यह जनकारी मिली। एक महीने पहले जुलाई में उपोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित युद्धान्वयन 6.71 प्रतिशत में 5.3 प्रतिशत थी।

कारवां, सारेगामा ने लॉन्च किया

सिलीगुड़ी, 13 सितम्बर। कारवां, सारेगामा ने एक उपयोगिता-आधारित उत्पाद कारवां निर्मला सीतामण पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें इस स्थिति में भी खुदरा नहीं दिखाई देता है तो वह औपसत भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करती। पूर्व वित्त मंत्री ने टीवी किया, अभी कुछ दिन पहले ही, माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई उनके लिए चिंता को कोई बढ़ा दिया नहीं है। आपको आधारित युद्धान्वयन 6.71 प्रतिशत में 5.3 प्रतिशत थी।

कारवां मोबाइल प्री-लोडेड गानों के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

कारवां मोबाइल प्री-लोडेड गानों के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री के कासम साथ चलाने के लिए।

लंबे समय तक चलाने वाले

कारवां मोबाइल के साथ अब तक का पहली की पैटेंड मोबाइल है और कारवां मोबाइल उन सभी मोबाइल में से एक है जो कांग्रेस वित्त मंत्री

आप ने गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का किया वादा



अहमदाबाद, 13 सितम्बर (एजेन्सी)। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्जविंद के जरीवाल ने मंगलवार को वादा किया कि अगर उनको पार्टी गुजरात में सता में आती है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे।

यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सरकार में कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिए होगा, वहाँ वह आपका हो या अन्य दलों का, उसे जेल भेजा जाएगा।

केरीवाल ने पंजाब सरकार के एक फैसले का भी हवाला दिया जब वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के लिए एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पब्लिक फंड का इस्तेमाल विकास के लिए ही किया जाएगा, इसे न तो कॉर्पोरेट मित्रों को वितरित कर्बांद कर ही रही है, वह वैसे ही है जैसे भाजपा की अनुमति दी जाएगी।

केरीवाल ने आरोप लगाया कि

अमेठी में अवैध रूप से बने मदरसे को किया गया ध्वस्त, अदालत के आदेश पर हुई कारवाई

अमेठी, 13 सितम्बर (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जिला प्रशासन ने चारगाह की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे को ध्वस्त कर दिया। गौरीगंज क्षेत्र में टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे गुर्जर टोला गांव में मदरसे को पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया।

यह मदरसा 2009 से चल रहा था। इसको लेकर एक स्थानीय अदालत में मामला चल रहा है। लेकिन पिछले दो साल से भवन में कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था।

अमेठी के जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्रा ने कहा, अदालत के आदेश के बाद, मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। यह एक चारगाह के लिए जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था।

अमेठी के प्रशासन ने मदरसे के मालिक पर 2.24 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त अन्य समस्याओं और किसी भी गैर-सरकारी संगठनों से उनकी संबद्धता के बारे में जनकारी एकत्र करने के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी के बिना वितरित किया गया है।

वह इन मदरसों के वित्तीय स्रोतों की भी जांच कर रही है।

ग्रामीण विकास विभाग

से आने वाले ग्रामीणों को हो रही समस्या के शीघ्र समाधान हेतु प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विभाग से कारबाही तर्फ से विभागीय अधिकारी को आरोप है कि वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्युत आपूर्ति के पिछले साल भर से उपरान्त राजस्थान और विभाग की नाकामी को ली रखा रहा है। इसके समाधान हेतु सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनके अनुसार सालाह भर में केवल एक ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाना विभाग की लापरवाही है। इसी कारण आज परिवर्तन सिक्किम के लोग अन्य विभिन्न सरकारी सुविधाओं से वर्चित हैं।

इसके साथ ही आपलोगों का यह भी कहना है कि जहाँ एक और वर्तमान सरकार एवं मुख्यमंत्री द्वारा जनता को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने तथा प्रशासन एवं विभाग से समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु कदम उठाने की बात कही जाती है, वहाँ दूसरी ओर इस प्रकार की घटनाओं से सरकार की बदनामी ही हो रही है। उनके अनुसार इस परिसर में ग्रामीण जनता से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सङ्काय विभाग, गोजिंग प्रखंड विकास विभाग एवं कई अन्य विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ऐसे में इस प्रकार की समस्या से ग्रामीणों को हो रही परेशानी चिंता की बात है।

साली पीढ़ी का भविष्य दांव पर है। उन्होंने कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं, अशांति नहीं चाहते लेकिन हम इस प्रकार कृत्य को भी बदल देने के लिए आधारी होंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के लाइसेंस रद्द कर दिए गए तो वह मित्रोंगांग जाएंगे और मुख्यमंत्री को खदा लगाकर उनका आभार प्रकट करेंगे। हालांकि उन्होंने सरकार पर सिक्किम के पक्ष में काम नहीं करने का भी आरोप लगाया।

सरकार समय पर ऐक्शन लेती तो बच जाती कई लोगों की जान, कोरोना पर गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेन्सी)। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अगर रोकथाम के उपायों को समय पर लागू किया जाता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। एक संसदीय समिति ने यह बात कही है। समिति ने हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाने के लिए सरकार की अलोचना भी की। स्वास्थ्य मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने सोमवार को राजसभा में 137वीं सिपोर्ट पेश की।

रिपोर्ट में कहा जाता है कि इसके कोई संदेश नहीं है कि कोविड की दूसरी

लहर के दौरान कई चीजों की अनदेखी हुई। इस दौरान संक्रमण और मौत के बढ़ते मामलों में बढ़ि, अस्पतालों में ऑक्सीजन व बिस्टरों की कमी, दवाओं व अन्य जस्ती विभाव के लिए लोगों की आपूर्ति का अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य देख खाल सेवाओं में स्कावट, ऑक्सीजन मिलेंड व दवाओं की जमाखोरी और कालावाजारी अदि देखी गई।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'समिति का विचार है कि अगर सरकार शुरुआती चरण में ही वायरस के अधिक संक्रामक स्वरूप की पहचान

कर पाती और रोकथाम रणनीति को करती है तो लगातार देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार कोविड-19 महामारी और इसकी लहरों के संभवित जोखिम का सटीक अनुमान नहीं लगा पाई।

समिति ने कहा कि भारत दुनिया में कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा। देश की विशाल आवादी के कारण महामारी के दौरान बड़ी चुनौती पेश की गई।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

कारण देश में जबरदस्त दबाव देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार कोविड-19 महामारी और इसकी लहरों के संभवित जोखिम का सटीक अनुमान नहीं लगा पाई। समिति ने कहा कि पहली लहर के बाद जब देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई, तब सरकार को देश में हालाती विभागीय कोर्ट द्वारा लोगों की सतर्कता बढ़ाई।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है, किंतु कोरोना के लिए सड़कों पर पदयात्रा करते हुए लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी

पहले प्रक्रिया पर नजर रखने के बाद देश की विचारी चरण में ही लोगों की दूरी नहीं है।

समिति ने कहा कि लचर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी क

बीमार सोच बदलनी होगी

नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी से शर्मिदा करने वाली एक और खबर आई है। ताजा मामले में आरोप है कि 38 साल की एक महिला ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकॉनमिक्स की प्रफेसर हैं, गेट खोलने में जरा सी देर होने पर सिक्यॉरिटी गार्ड को न केवल गालियां दीं बल्कि कई थख्खपट् जड़ दिए। नोएडा की अलग-अलग सोसाइटी से इस तरह की कई खबरें पिछले कुछ समय में आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक विडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला वकील ने इसी तरह सिक्यॉरिटी गार्ड्स के साथ बदसलूकी की और उन्हें गालियां दी थीं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं, जो पुलिस तक नहीं पहुंचतीं या जिनके विडियो वायरल नहीं होते। मगर ये बताती हैं कि राजधानी दिल्ली के चारों ओर बनी गगनचुंबी इमारतों और महंगी हाउसिंग सोसाइटियों में रह रही समाज की अपेक्षाकृत संपत्ति आबादी के एक हिस्से में बेहद बीमार सोच पल रही है। इसी सोच की झिलक हमें कभी किसी पुरुष द्वारा महिला के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल में दिखती है तो कभी किसी नशे में धुत महिला द्वारा सिक्यॉरिटी गार्ड्स को उनकी औकात बताने की भद्दी कोशिश में।

वैसे, हाल की कुछ घटनाएं भले नोएडा और आसपास की हों, यह बीमारी देश के अन्य हिस्सों में भी फैली हुई है। मुंबई जैसे शहर इस लिहाज से आम तौर पर काफी संयत माने जाते हैं लेकिन भेदभाव के अलग-अलग रूप उन शहरों की तथाकथित हाई क्लास सोसाइटियों में भी देखे जाते रहे हैं। काम वाली बाइयों, स्टाफ के अन्य कर्मचारियों और उनके परिजनों के आने-जाने के लिए अलग रस्ते और अलग लिफ्ट की व्यवस्था इसी भेदभाव भरी सोच का उदाहरण है। ऐसे ही बड़े शहरों में किराए पर मकान देते हुए जिस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं, वे भी सोच की इन गड़बड़ियों के सबूत हैं। इन शर्तों में न केवल शादीशुदा जोड़ों या परिवार को ही किराये पर मकान या फ्लैट देने का आग्रह दिखता है बल्कि सिंगल लोगों, खासकर लड़कियों पर मोरल पुलिसिंग लादने की प्रवृत्ति भी दिखती है। इसके साथ ही खास जाति या धर्म के लोगों को मकान और फ्लैट न बेचने या किराए पर न देने की मानसिकता भी प्रमुखता से झिलकती है। ये सब हमारे समाज की ऐसी गड़बड़ियों हैं जो लंबे समय से मौजूद हैं, लेकिन आजादी के बाद देश के विकास के साथ आए आधुनिक और प्रगतिशील मूल्यों के प्रभाव में धूंधली पड़ती जा रही थीं। अफसोस और चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय से यह क्रम उलटा शुरू हो गया लगता है। यानी ये गड़बड़ियां जो कम हो रही थीं, अब फिर से जोर पकड़ती दिखने लगी हैं। चाहे जिस किसी भी बहाने से हो खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने की यह सोच खतरनाक है। यह समाज के रूप में हमारी सारी उपलब्धियों पर पानी फेर सकती है। इसका कोई न कोई इलाज जल्द से जल्द हूंडना होगा।

फिर वही जुड़ाव तलाशती पदयात्रा

रशीद किंवद्दि

सुरु दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी इस यात्रा से अगले 150 दिनों में कीरब 3,500 किलोमीटर की दूरी नापेंगे। इसके जरिये महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक धूकीरण जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार व भारतीय जनता पार्टी को धोए तो जागा ही, कांग्रेस पार्टी के संगठन में प्राण फूंकने के प्रयास भी किए जाएंगे। सबाल है कि क्या यह यात्रा पार्टी को नई संजीवी दे सकेगी?

दरअसल, भारत में राजनीतिक यात्राएं लंबे समय से होती रही हैं। मगर सूचना क्रांति के बाद इनका उद्देश्य बहुत कुछ बदल चुका है। महात्मा गांधी, एनटी रामाराव, लालकृष्ण आडवाणी, सुनील दत्त, राजीव गांधी, चंद्रशेखर जैसी तमाम शख्सियतों ने राजनीतिक यात्राएं कीं, जैसे कि उन्हें लोगों तक अपनी बात दिखानी थी। उस वक्त सूचना तंत्र दिखाने के लिए उनको उत्तराखण्ड की ओर भी कई लोगों पर धोए गए। यह यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगी और 12 राज्यों से गुजरते हुए हिमाचल के चुनाव प्रचार के लिए भी सकते हैं। मगर इस बार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा बढ़ावा देने का फैसला किया है। वह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखा रही है। इस कारण यह भी पूछा जा रहा है कि कहाँ सियासी पिंच पर विफल रहने के आरोपों से वह दुखी तो नहीं हैं या आत्मविश्वास तो नहीं हार रहे हैं?

हालांकि, यह यात्रा राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होने वाली। उनको कई मोर्चों पर जूँड़ा पड़ सकता है। मध्यस्थ यात्रा के बाद से ही उनका मज़ाक उड़ाने के लिए एक पूरा तंत्र तैयार किया गया है, और लोग उसके आधार पर अपनी राय बनाने लगते हैं। इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी खबर किया जाता है। लिहाज अब यात्राएं काफी सोच-समझकर निकाली जाने लगी हैं।

अगर यात्रा अध्यक्षतम के प्रचार-प्रसार, चिंतन या कुछ सोखने की मांश के साथ शुरू की गई हो, तो

वह अमूमन सफल होती है। मगर राजनीतिक यात्राओं के साथ दिक्कत यह है कि उनको चुनावी जीत-हार के पैमाने पर तौला जाता है। कांग्रेस की यात्रा का भी यही मापदंड है। अगले तीन-चार महीनों में गुजरात और हिमाचल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 182 सीटों में 77 सीटें इसलिए मिल सकी थीं, जैसे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा बढ़ावा देने का फैसला किया है। वह पूरी यात्रा में मौजूद रह सकते हैं, ताकि कांग्रेस के विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हां, बीच में वह गुजरात और हिमाचल के चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर हो रही थी, इसलिए वहां से तब यात्रा की शुरूआत की गई थी। इसके लिए राजीव गांधी ने सत्ता से चुनिंदा हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने 197 सीटें जीती थीं। चूंकि उन्होंने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। और पार्टी अध्यक्ष की चुनाव-प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं।

टकराना होगा, क्योंकि वह लगातार उनकी आलोचना करता रहा है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी थक्कर करते हैं। वह यात्रा के लिए जांच बढ़ावा देने का फैसला किया है। वह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखा रही है। इस कारण यह भी पूछा जा रहा है कि कहाँ सियासी पिंच पर विफल रहने के आरोपों से वह दुखी तो नहीं हैं या आत्मविश्वास तो नहीं हार रहे हैं?

हालांकि, यह यात्रा जांच बढ़ावा देने का फैसला किया है। उनको उत्सुकता नहीं होने वाली। उनको कई मोर्चों पर जूँड़ा पड़ सकता है। मध्यस्थ यात्रा के बाद से ही उनका मज़ाक उड़ाने के लिए एक पूरा तंत्र तैयार किया गया है, और लोग उसके आधार पर अपनी राय बनाने लगते हैं। इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी खबर किया जाता है। लिहाज अब यात्राएं काफी सोच-समझकर निकाली जाने लगी हैं।

अगर यात्रा अध्यक्षतम के प्रचार-प्रसार, चिंतन या कुछ सोखने की मांश के साथ शुरू की गई हो, तो

जरूर सौंपा, लेकिन इसे मित्रभाव

का एक नमूना माना जाना चाहिए।

कुछ लोग राहुल गांधी की इस यात्रा की तुलना राजीव गांधी की 1990 की सद्दावाना यात्रा से करने लगे हैं, जो गलत है। राजीव गांधी बेशक 1989 के आम चुनाव में सत्ता से चुनिंदा हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने 197 सीटें जीती थीं। चूंकि उन्होंने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। और पार्टी अध्यक्ष की चुनाव-प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए राजीव गांधी ने गुजरात में चुनाव होने हैं। वह पूरी यात्रा में मौजूद रह सकते हैं, ताकि कांग्रेस के विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हां, बीच में वह गुजरात और हिमाचल के चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। और पार्टी अध्यक्ष की चुनाव-प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं।



प्रसारित किए जाते हैं, तब उसका सीधा असर होता है। भाजपा की बतें लोगों को इसलिए उत्साहित करती हैं, वैसोंकि वे उनको आसानी से समझ में आ जाती हैं। यह यात्रा की तुलना चुनाव में आ जाती है। संप्रदाय, जाति या क्षेत्र के आधार पर वह मतदाता नहीं बनती। पहले ये चीजें कांग्रेस की ताकत हुआ करती थीं, पर वैसोंकि वे अपनी बनाने के लिए आत्मारक्षणिक थीं। यह यात्रा की तुलना चुनाव में आ जाती है। यह यात्रा का ताकत हुआ करता है। इसलिए 2024 का आम चुनाव ही इस यात्रा का नतीजा बताएगा। हमें यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी की ताकत को बढ़ावा देंगे। इसकी ताकत नहीं करता है।

कृषि जोड़ सकती है दक्षिण एशिया को

पत्रेलेखा चट्टर्जी

हम दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट करने के लिए हमेसा क्रिकेट और भारतीय विधानसभा के बारे में सोचते हैं, भले अन्य मुद्दों पर उनके विचार अलग ही बोलें न हों। ऐसे समय में जब वैश्विक खाद्य संकट के लिए उनका उत्तराखण्ड के लिए एक बड़ी रणनीति है। इसमें योगेंद्र यादव, अरुणा रॉय जैसे सिविल सोसाइटी आडवाणी के लोगों ने योगेंद्र यादव के लिए एक बड़ी रणनीतिक रणनीति बनाई है। उनको उत्तराखण्ड के लिए एक बड़ी रणनीतिक रणनीति बनानी च



ऋतिक की फाइटर से टकराएगी प्रभास की सालार

बीते सालों में साउथ सिनेमा बॉलीवुड पर भारी पड़ता नजर आया है, जिस वजह से बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारों में कांटे की टक्के देखने को मिल रही है। सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म 'सालार' की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर प्रभास और उनकी फिल्म ट्रॉड कर रही है। 'सालार' अगले साल 28 सितंबर को पर्दे पर दस्तक देगी, यह सुनकर ऋतिक रोशन की मुश्किलें यकीन बढ़ गई होंगी। इसके पीछे का कारण है ऋतिक और प्रभास की फिल्मों के बीच होने वाला बैलैश। प्रभास की 'सालार' और ऋतिक की 'फाइटर' दोनों ही फिल्में अगले साल सितंबर में एक ही दिन रिलीज होने वाली हैं, जिसका असर कलेक्शन पर भी नजर आ सकता है। दरअसल, दोनों एक्टर्स की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्के देखने को मिलेगी। इसके अलावा बायकॉट बॉलीवुड ट्रॉड को देखते हुए ऋतिक रोशन के लिए बॉक्स ऑफिस पर सालार का सम्मान करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' में कौन बना है संजय गांधी? एकट्रेस ने तस्वीर शेयर करते सबको चौंकाया

बॉलीवुड एकट्रेस कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर चर्चा में है। कंगना ने अपनी फिल्म का छोटा सा टीजर रिलीज किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म एक राजनीतिक ड्रामा है जो भारत में 1975 में लगे आपातकाल पर आधारित है। फिल्म के मुख्य कलाकारों के लुक को एक-एक करके शेयर किया जा रहा है। कंगना थीरे-थीरे अपनी फिल्म के किरदारों से पदों उठा रही हैं और सोशल मीडिया पर उनके लुक्स शेयर करती रही हैं। उन्होंने अब राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की भूमिका में विशेष नायर को पेश किया है। विशेष नायर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना नुक शेयर किया। पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'संजय गांधी की भूमिका निभाने के लिए वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जैसे ही उन्होंने तस्वीर की प्रशंसकों ने बधाई की शुभकामनाओं के साथ कमेंट रेक्षण में खूब कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, 'दा आप पर बहुत खुशी और गर्व है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हे भगवान! बधाई।' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'यह फिल्म जरुर हिट होगी। सभी किरदार बिल्फूल मेल खाते हैं। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के रूप में कंगना रनौत, जेपी नाराणण के रूप में अनुपम खेर, पुपुल जयकर के रूप में महिमा चौधरी, अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में श्रेयस तलाड़े, और मिलिंद सोमन फील्ड मार्शल सैम मानेकशों की भूमिका निभाएंगे। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आगामी जीवनी कंगना रनौत द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म का समर्थन रेणु पिटी और कंगना ने किया है।

किशोरों को वयस्क जेलों में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय अदालतों द्वारा बताई जाने वाली सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है, और किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को कहीं अधिक व्यापक व्याचिका मिली है और आज स्वीकार की गई धारणा यह है कि स्वतंत्रता में वे अधिकार और विशेषाधिकार शामिल हैं, जिन्हें लंबे समय से एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा खुशी की व्यवस्थित खांजे के लिए आवश्यक माना जाता है।

पीठ ने सोमवार को दिए एक फैसले में कहा, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है।

पीठ ने कहा कि किशोर न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों में बच्चे के अधिकारों और संवंधित कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक बार बच्चा वयस्क आपाधिक न्याय प्रणाली के जाल में फँस जाता है, तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।

शीर्ष अदालत ने एक हत्या के



दोषी की याचिका पर सुनाई दिये गयी पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखखाव) नियम, 1970 के नाबालिंग होने का दावा किया था। याचिकाकर्ता, जिसकी सजा को 2016 में शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा, उसने कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी सही उम्र के सत्यापन के लिए निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता विनोद कट्टरा की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषि मल्हारा ने कहा कि उनके मुख्यक्रिया ने किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

शीर्ष अदालत ने चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह रिकार्ड पर रखे गए दस्तावेजी सबूत हैं जो कानून के संबंध में एक किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

शीर्ष अदालत ने चिकित्सा आयु संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के संबंध में इस समय भी इस तरह की याचिका दायर करने की अनुमति दे रहा है।

याचिकाकर्ता को परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ, जहां उसका जन्म वर्ष 1968 दिखाया गया था, और दावा किया कि अपाधिक के समय वह 14 वर्ष का प्रमुख होना जरूरी है।

आगे कहा गया, हम आगरा के सत्र न्यायालय को इस आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर कानून के संबंध में रिट आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करने का निर्देश देते हैं।

शीर्ष अदालत ने सत्र अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गए विवरों को सत्यापित करने का निर्देश दिया।

ज्ञानवापी मामला: महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, बोलीं- बीजेपी के एजेंडे में है



जम्मू, 13 सितम्बर (एजेंसी)। शीर्ष पुलिस डे मोक्षिक टार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने कानून के रैखिक स्थल अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के धृतीकरण के एजेंडे को पूरा करता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट पार्टी के देश के लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि भाजपा हिन्दूओं और मुसलमानों को बांटने में सबसे आगे है और अपने हितों के लिए संविधान को कुचल रही है।

कोर्ट ने कहा कि यह रिकार्ड पर रखे गए दस्तावेजी सबूत हैं जो कानून के संबंध में एक किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

शीर्ष अदालत ने चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का परीक्षण तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक डॉक्टर को रेडियोलॉजी विभाग का प्रमुख होना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी शंगार गौरी मामले की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि इसी तरह बनी रही, तो हम किसी अन्य चीज के बजाय मस्जिदों को तोड़ने में विश्वगुरु' बन सकते हैं।'

उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने दो सोमवार को ज्ञानवापी शंगार गौरी मामले की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि इस तरह की याचिका दायर करने के बावेदक के किशोर होने के दावे की जांच करने का निर्देश देते हैं।

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश को याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गए विवरों को सत्यापित करने का निर्देश दिया।

उदालत ने कहा कि यह विवरों के लिए एक विवरणीय विवरण है।

खिलाफ कोई अशोभायी व्यापार दिये गये तो हम तदनुसार जवाब देंगे। यही हमारा स्तर है। माकपा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा' की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा था कि वाम सांसारिकी के अन्तर्गत ज्ञानवापी शंगार गौरी मामले को आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले। माकपा की केरल इक्वार्ड ने मंगलवार को कहा कि उनके पास इस यात्रा का विरोध करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ किसी अनुचित आलोचना या अशोभायी व्यापार को देखनी चाही रही है।

माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक व्याख्यान दिया है। इस द्वीप में केरल और उत्तर प्रदेश के नरसों थे और उनके क्षेत्रफल के अंतर को दर्शाया गया था। इस द्वीप के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हालांकि अगर पार्टी, उसके वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या वाम मोर्चा की अनुचित आलोचना हुई है।

माकपा के प्रेस संचिव एम वी गोविंदन ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी का रुख यात्रा के खिलाफ या इससे जुड़ी किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि अगर पार्टी, उसके वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या वाम मोर्चा की अनुचित आलोचना हुई है तो उसके खिलाफ किसी अनुचित आलोचना नहीं है।

माकपा के प्रेस संचिव एम वी गोविंदन ने दो सोमवार को कहा कि इसके विवरों के खिलाफ या इससे जुड़ी किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके विवरों के खिलाफ या इससे जुड़ी किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है।

माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक व्याख्यान दिया है। इस द्वीप में केरल और उत्तर प्रदेश के नरसों थे और उनके क्षेत्रफल के अंतर को दर्शाया गया था। इस द्वीप के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हालांकि अगर पार्टी, उसके वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या वाम मोर्चा की अनुचित आलोचना हुई है।

माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक व्याख्यान दिया है। इस द्वीप में केरल और उत्तर प्रदेश के नरसों थे और उनके क्षेत्रफल के अंतर को दर्शाया गया था। इस द्वीप के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हालांकि अगर पार्टी, उसके वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या वाम मोर्चा की अनुचित आलोचना हुई है।

माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक व्याख्यान दिया है। इस द्वीप में केरल और उत्तर प्रदेश के नरसों थे और उनके क्षेत्रफल के अंतर को दर्शाया गया था। इस द्वीप के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हालांकि अगर पार्टी, उसके वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या वाम मोर्चा की अनुचित आलोचना हुई है।

माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक व्याख्यान दिया है। इस द्वीप में केरल और उत्तर प्रदेश के नरसों थे और उनके क्षेत्रफल के अंतर को दर्शाया गया था। इस द्वीप के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हालांकि अगर पार्टी, उसके वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या वाम मोर्चा की अनुचित आलोचना हुई है।

माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक व्याख्यान दिया है। इस द्वीप में केरल और उत्तर प्रदेश के नरसों थे और उनके क्षेत्रफल के अंतर को दर्शाया गया था। इस द्वीप के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हालांकि अगर पार्टी, उसके वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या वाम मोर्चा की अनुचित आलोचना हुई है।

माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक व्याख्यान दिया है। इस द्वीप में केरल और उत्तर प्रदेश के नरसों थे और उनके क्षेत्रफल के अंतर को दर्शाया गया था। इस द्वीप के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हालांकि अगर पार्टी, उसके वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या वाम मोर्चा की अनुचित आलोचना हुई है।

माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक व्याख्यान दिया है। इस द्वीप में केरल और उत्तर प्रदेश के नरसों थे और उनके क्षेत्रफल के अंतर को दर्शाया गया था। इस द्वीप के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ह